



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1940 (श10)
(सं0 पटना 527) पटना, वृहस्पतिवार 7 जून 2018

सं0 08/आरोप-01-27/2017 सा0प्र0-1556

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 फरवरी 2018

श्री योगेन्द्र पाण्डेय, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-307/04 (सेवानिवृत्त दिनांक 31.12.2004) के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता-सह-नजारत उप समाहर्ता, पुपरी अनुमंडल के पदस्थापन काल में सेवा निवृत्त/मृत चौकीदारों/दफादारों के लिए भुगतये गुप बीमा एवं अव्यवहृत अर्जित अवकाश के लिए नगद राशि के गबन का आरोप जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-367 दिनांक 02.12.2002 द्वारा प्राप्त हुआ। इस क्रम में पुपरी थाना कांड सं०-95/02 दर्ज होने की सूचना भी प्राप्त हुई। विभागीय स्तर पर उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत संकल्प ज्ञापांक-5480 दिनांक 10.06.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-537 दिनांक 03.07.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें आरोप की घटना के विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की तिथि (10.06.2009) से चार वर्ष पहले घटित होने के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-1893 दिनांक 14.06.2011 के आलोक में कालबाधित होने का मंतव्य दिया गया।

विभागीय स्तर पर समीक्षा के क्रम में सदृश्य मामले (तारा रजक, बि०प्र०से०) में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रदत्त मंतव्य निम्नवत् पाया गया :-

" There is no Provision for condonation of delay in initiating the departmental proceeding against law. The Provision of condonation of delay only applies in Judicial Proceedings.

Under the circumstances I am of the opinion that as per the existing Rules 43 (b) and 139 (a) of the Bihar Pension Rules, the initiation of proceedings itself was illegal and the department may not proceed any further in the matter in view of the reason already stated above."

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री योगेन्द्र पाण्डेय, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-307/04 (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध संकल्प ज्ञापांक-5480 दिनांक 10.06.2009 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है। इस संबंध में दर्ज आपराधिक मामला (पुपरी थाना कांड सं०-95/02) से उद्भूत न्यायिक वाद में आदेश पारित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 527-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>